2017 में संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का विश्लेषण

भारत के राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने 31 जनवरी, 2017 को संसद को संबोधित किया था।[1] अपने अभिभाषण में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की मुख्य नीतिगत प्राथमिकताओं को रेखांकित किया था। निम्नलिखित तालिका में 2017 में राष्ट्रपति के अभिभाषण के मुख्य विषयों और उन विषयों के संबंध में की गई पहल की मौजूदा स्थिति को प्रस्तुत किया गया है। 27 जनवरी, 2018 तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर इस नोट को तैयार किया गया है। आंकड़ों के स्रोत एंड नोट्स में दर्ज किए गए हैं।

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
	अर्थव्यवस्था और वित
2014 से मुद्रास्फीति, भुगतान संतुलन, राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा निरंतर कम हुआ है	▪ **मुद्रास्फीति:** आरबीआई ने 2016-2021 की अवधि के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआई) का लक्ष्य 4% अधिसूचित किया था।[2] भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के उच्च स्तर को 6% और निम्न स्तर को 2% पर निर्धारित किया था।[2] ▪ 2017-18 की पहली तीन तिमाही में सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति इस प्रकार थी: (i) 2.2% (अप्रैल-जून); (ii) 2.9% (जुलाई-सितंबर); और (iii) 4.5% (अक्टूबर-दिसंबर)। 2016-17 के संबंधित आंकड़े इस प्रकार थे: (i) 5.7%; (ii) 5.1%; और (iii) 3.7%.[3] ▪ 2017-18 की पहली तीन तिमाही में खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति इस प्रकार रही: (i) -0.9% (अप्रैल-जून); (ii) 0.8% (जुलाई-सितंबर); और (iii) 3.8% (अक्टूबर-दिसंबर)। 2016-17 के संबंधित आंकड़े इस प्रकार थे: (i) 7.1%; (ii) 6%; और (iii) 2.2%।[3] ▪ **राजकोषीय घाटा:** 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.2% (5,46,532 करोड़ रुपए) पर लक्षित है (2016-17 में यह 3.5% था)।[4] सरकार ने नवंबर 2017 में अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार कर लिया था।[5] 2017-18 के केंद्रीय बजट

गायत्री मान gayatri@prsindia.org
सनत कंवर sanat@prsindia.org

27 जनवरी, 2018

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है जून 2016 में विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई के नीतिगत प्रावधान उदार किए गए	में प्रस्तुत किए गए अनुमानों की तुलना में राजकोषीय घाटा 112% पर रहा।[5] उपलब्ध प्रोविजनल अनुमानों के अनुसार, 2016-17 में सरकार ने अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 794 करोड़ रुपए (0.1%) तक बढ़ा लिया।[6] ▪ **चालू खाता घाटा (सीएडी):** 2017-18 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में सीएडी बढ़कर 14.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि 2016-17 की पहली तिमाही में यह 0.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।[7] 2017-18 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में यह बढ़कर 7.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि 2016-17 की दूसरी तिमाही में यह 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।[8] ▪ **विदेशी मुद्रा भंडार:** 5 जनवरी, 2018 तक के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार पिछले एक वर्ष की तुलना में 6.6% बढ़ गया और 26 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। पिछले वर्ष 6 जनवरी तक यह आंकड़ा 24.4 लाख करोड़ रुपए था।[9] ▪ **विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई):** 2017-18 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में एफडीआई 25.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, जबकि 2016-17 में इसी अवधि के दौरान यह आंकड़ा 21.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।[10,11] ▪ इस वर्ष सरकार ने एफडीआई नीति में कुछ परिवर्तन किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं (i) एकल ब्रांड खुदरा व्यापार के लिए ऑटोमैटिक रूट के अंतर्गत 100% एफडीआई को मंजूरी, और (ii) जनवरी 2018 में विदेशी एयरलाइन्स को एयर इंडिया में 49% तक निवेश करने को मंजूरी।[12]
ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार, नकली करंसी और आतंकवाद के वित्त पोषण पर काबू पाने के लिए 500 रुपए और 1,000 रुपए के करंसी नोटों को विमुद्रित किया गया	▪ विमुद्रीकरण से पहले सर्कुलेशन वाले 500 रुपए और 1,000 रुपए के करंसी नोट, कुल नोटों का 86% थे।[13] ▪ आरबीआई की 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट का कहना है कि 30 जून, 2017 तक 15.3 लाख करोड़ रुपए के विमुद्रित नोट (500 और 1,000 रुपए) (98.9%)

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
	आरबीआई में वापस आ आए। रिपोर्ट कहती है कि जून 2017 तक अनुमानित 16,000 करोड़ रुपए के विमुद्रित नोट वापस नहीं आए।[14,15] ▪ नवंबर 2016 से अक्टूबर 2017 की अवधि के दौरान 24,800 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला था।[16] ▪ नवंबर 2017 तक 3.89 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स ई-रिटर्न फाइल किया गया, जबकि 2016-17 में इसी अवधि के दौरान 3.25 करोड़ रुपए का ई-रिटर्न फाइल किया गया था (19.7% की वृद्धि)।[16]
एक देश एक टैक्स और एक देश-एक बाजार के जरिए सहकारी संघवाद की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए संसद के दोनों सदनों ने वस्तु एवं सेवा कर एक्ट पारित किया	▪ देश भर में 1 जुलाई, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को प्रस्तावित किया गया।[17] ▪ 2017-18 के लिए 12,27,014 करोड़ रुपए के कर राजस्व का अनुमान था।[18] नवंबर 2017 तक जीएसटी टैक्स कलेक्शन (केंद्र का हिस्सा) 4,41,036 करोड़ रुपए था।[19,20,21,22,23]
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को प्रस्तावित करने वाला टैक्सेशन कानून (दूसरा संशोधन) एक्ट, 2016 ब्लैक मनी से लड़ने की व्यापक नीति तैयार करेगा	▪ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत एकत्र राशि का सरकारी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपए एकत्र किए गए हैं।[24,25]
व्यापार संबंधी बाधाओं को चिन्हित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ कार्य किया जा रहा है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग से प्रदर्शित होता है कि सुधारों का राष्ट्रीय कार्यान्वयन औसत लगभग 49% है, जबकि पिछले वर्ष यह 32% था	▪ अक्टूबर 2017 में विश्व बैंक ने अपनी वार्षिक 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में इस वर्ष भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। 190 देशों की सूची में इस वर्ष भारत का स्थान 100वां है। पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 130 थी।[26,27] ▪ रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने कुछ मानदंडों में परिवर्तन प्रस्तावित किए हैं जिनके कारण उसकी बिजनेस रैंकिंग में वृद्धि हुई है। इन परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल है : (i) इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता 2016 को पारित करना जिसके अंतर्गत इनसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए 180 दिन की समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान की जाती है, (ii) इंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड के भुगतान को इलेक्ट्रॉनिक बनाया गया, और (iii) कॉरपोरेट आय कर के अनुपालन को आसान करने के उपाय प्रस्तावित किए गए, इत्यादि।[28,29,30]

<table>
<tr><th>नीतिगत प्राथमिकता</th><th>मौजूदा स्थिति</th></tr>
<tr><td>अप्रत्याशित 26 करोड़ जन धन खाते खोले गए हैं</td><td>▪ प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रारंभ से 25 जनवरी, 2018 तक इस योजना के अंतर्गत 31 करोड़ खाते खोले गए (इसमें 2017-18 में खोले गए 5 करोड़ खाते भी शामिल हैं)। इनमें से 59% खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए।[31]
तालिका 1: जन धन योजना के अंतर्गत उपलब्धियां (2014-18)[32]
<table>
<tr><th></th><th>जनवरी-15</th><th>जनवरी-16</th><th>जनवरी-17</th><th>जनवरी-18</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>खोले गए खातों की संख्या</td><td>11,31,37,733</td><td>8,88,04,329</td><td>6,48,76,175</td><td>4,24,96,818</td><td>30,93,15,055</td></tr>
<tr><td>जमा की गई राशि (रुपए करोड़ में)</td><td>8,899</td><td>21,209</td><td>38,919</td><td>4,231</td><td>73,258</td></tr>
</table>
Note: The data for 2017-18 is updated till January 25, 2018.
▪ 15 जुलाई, 2018 तक 23.3 करोड़ रुपए मूल्य के रूपे डेबिट कार्ड जारी किए गए (इसमें 2017-18 में खोले गए 3.3 करोड़ खाते शामिल हैं)।[31]</td></tr>
<tr><td>20 करोड़ से अधिक रूपे डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं</td><td></td></tr>
<tr><td>जन धन-आधार-मोबाइल (जैम) ट्रिनिटी का प्रयोग करते हुए डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर किए गए जिससे लीकेज रुका और 36,000 करोड़ रुपए की बचत हुई</td><td>▪ 25 जनवरी, 2017 तक 411 योजनाओं के अंतर्गत (जब से उन्हें प्रारंभ किया गया) लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) कार्यक्रम के जरिए 2.7 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए।[33,34]
▪ सरकार के अनुसार, इस कार्यक्रम से पिछले तीन वर्षों में 57,000 करोड़ रुपए की कुल राशि की बचत हुई। इस प्रक्रिया के जरिए 2.3 करोड़ नकली राशन कार्ड और 3 करोड़ नकली एलपीजी कनेक्शन चिन्हित किए गए।[33]
तालिका 2: डीबीटी के जरिए वितरित राशि (2014-17) (करोड़ रुपए में)[34]
<table>
<tr><th></th><th>2014-15</th><th>2015-16</th><th>2016-17</th><th>2017-18</th></tr>
<tr><td>डीबीटी के जरिए वितरित राशि</td><td>38,926</td><td>61,942</td><td>74,707</td><td>89,764</td></tr>
</table>
Note: The data for 2017-18 is updated till January 25, 2018.</td></tr>
<tr><td>प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 5.6 करोड़ ऋण मंजूर किए गए और इसके तहत 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई</td><td>▪ 23 जनवरी, 2018 तक योजना के अंतर्गत 10.5 करोड़ से अधिक ऋण मंजूर किए गए। मंजूर की गई कुल राशि 4.7 लाख करोड़ रुपए की है।[35] इसमें से 4.5 लाख करोड़ रुपए (96%) वितरित किए गए।[35]
▪</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>नीतिगत प्राथमिकता</th><th>मौजूदा स्थिति</th></tr>
<tr><td></td><td>तालिका 3: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत उपलब्धियां (2015-2018)[35]
<table>
<tr><th></th><th>2015-16</th><th>2016-17</th><th>2017-18</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>ऋण संख्या</td><td>3,48,80,924</td><td>3,97,01,047</td><td>3,03,32,003</td><td>10,49,13,974</td></tr>
<tr><td>मंजूर राशि (करोड़ रुपए में)</td><td>1,37,449</td><td>1,80,529</td><td>1,50,030</td><td>4,68,008</td></tr>
<tr><td>वितरित राशि (करोड़ रुपए में)</td><td>1,32,955</td><td>1,75,312</td><td>1,44,355</td><td>4,52,622</td></tr>
</table>
Note: The data for 2017-18 is updated till January 23, 2018.</td></tr>
<tr><td>विश्व की सबसे बड़ी कैश बेनेफिट ट्रांसफर स्कीम पहल से दो वर्षों में 21,000 करोड़ रुपए की बचत हुई</td><td>▪ पहल योजना जून 2013 में प्रारंभ की गई जिसके दायरे में अब तक 291 जिले आ चुके हैं। योजना के अंतर्गत एलपीजी सब्सिडी लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपने बैंक खातों से आधार नंबर को अनिवार्य रूप से लिंक कराना होता है।[36]
▪ 29 दिसंबर, 2017 तक कुल एलपीजी उपभोक्ताओं (21 करोड़) में से 94% पहल योजना में शामिल हो चुके हैं।[37,38]
▪ सरकार के अनुसार पिछले तीन वर्षों में पहल के लागू होने के कारण एलपीजी सब्सिडी से लगभग 29,446 करोड़ रुपए की बचत हुई है।[37]</td></tr>
<tr><td>1.5 लाख से अधिक पोस्ट ऑफिसों में पोस्टल बैंक स्थापित करने के लिए भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक शुरू किया गया</td><td>▪ भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) द्वारा सितंबर 2017 तक 650 जिलों में पोस्टल बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव था।[39]
▪ 3 जनवरी, 2018 तक आईपीपीबी ने 2 पायलट शाखाएं शुरू कीं।[39,40] सभी 650 शाखाओं को अप्रैल 2018 तक शुरू करने का प्रस्ताव है।[39]</td></tr>
<tr><td>डिजिटिल पेमेंट को सक्षम बनाने के लिए भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) नामक मोबाइल एप शुरू किया गया</td><td>▪ 18 अक्टूबर, 2017 तक भीम द्वारा रोजाना 25.6 लाख डिजिटल लेनदेन किए जाते थे, जबकि 8 नवंबर, 2016 में यह आंकड़ा 4,000 प्रति दिन का था।[41]</td></tr>
<tr><td colspan="2">शहरी और ग्रामीण विकास</td></tr>
<tr><td>स्वच्छ भारत मिशन- 1.4 लाख गांवों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया</td><td>▪ अक्टूबर 2014 में प्रारंभ किए गए स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) का लक्ष्य खुले में शौच को समाप्त करना और 2 अक्टूबर, 2019 तक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन करना है।[42,43]</td></tr>
</table>

	▪ नवंबर 2017 तक के आंकड़ों के अनुसार, रोजाना उत्सर्जित होने वाले 22% म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है।[44] ▪ 2017-18 में निर्मित हुए शौचालयों में 77% ग्रामीण घरों में बनाए गए, जबकि 2014 में यह आंकड़ा 44% था।[45] नीचे तालिका में 2014-15 से 2017-18 के बीच एसबीएम-ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित शौचालयों की संख्या प्रदर्शित की गई है। **तालिका 4: एसबीएम ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित शौचालयों की संख्या[46]** Note: Data for 2017-18 updated till January 24, 2018. ▪ 23 जनवरी, 2018 तक 6,04,219 में से 3,12,569 (52%) गांवों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया। इनमें से 65% गांवों को सत्यापित कर लिया गया।[46] निम्नलिखित तालिका में ओडीएफ गांवों की संख्या प्रदर्शित की गई है। **तालिका 5: ओडीएफ गांवों की संख्या[46]** Note: Data for 2017-18 updated till January 24, 2018.
शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 500 शहरों के लिए वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी गई	▪ 2015-2020 की अवधि के लिए स्मार्ट सिटीज़ और अमृत हेतु क्रमशः 48,000 करोड़ रुपए और 50,000 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।[47] ▪ 19 जनवरी, 2018 तक 99 स्मार्ट सिटीज को चुना गया है।[48] निम्नलिखित तालिका में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जारी की गई राशि को प्रदर्शित किया गया है। **तालिका 6: स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जारी राशि (करोड़ रु. में)[49]** Note: Data for 2017-18 updated till January 2, 2018 ▪ अमृत योजना प्रॉजेक्ट आधारित एप्रोच के जरिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाओं और गवर्नेंस संबंधी सुधारों को विकसित करने पर केंद्रित है।[47] इसके लिए राज्य की वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) के आधार पर राज्यों को धनराशि जारी की जाती

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
निर्मित शौचालयों की संख्या	49,01,277	1,25,67,031	2,18,29,519	2,03,25,774

	2015-16	2016-17	2017-18	कुल
घोषित ओडीएफ गांव	47,127	1,37,236	1,28,206	3,12,569
सत्यापित ओडीएफ गांव	17,887 (38%)	65,291 (48%)	1,20,948 (94%)	2,04,126 (65%)

अवधि	2015-16	2016-17	2017-18	कुल
जारी राशि	1,470	4,492	3,977	**9,940**

	है। 30 नवंबर, 2017 तक 164 करोड़ रुपए मूल्य के कुल 289 काम पूरे कर लिए हैं।[50]
प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए प्रत्येक बेघर गरीब को आश्रय देना	▪ 2022 तक सभी को आवास देने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) शुरू की गई थी। इसके दो अंग हैं- पीएमएवाई-शहरी और पीएमएवाई—ग्रामीण। ▪ पीएमएवाई—ग्रामीण को नवंबर 2016 में प्रारंभ किया गया था।[51] निम्नलिखित तालिका यह प्रदर्शित करती है कि लक्ष्य की तुलना में कितने घर बनाए गए। 2017-18 में प्रस्तावित घरों में से 11% घर बनाए गए थे, जबकि 2016-17 में 30% घर बनाए गए थे (यह आंकड़ा 24 जनवरी, 2018 तक का है)।[52] **तालिका 7: पीएमएवाई-ग्रामीण के अंतर्गत प्रगति[52]** **अवधि** | **2016-17** | **2017-18** **लक्ष्य** | 43,58,324 | 32,30,293 **उपलब्धि** | 13,14,066 (30%) | 3,71,460 (11%) Note: Data for 2017-18 updated till January 24, 2018. ▪ पीएमएवाई-शहरी को जून 2015 में शुरू किया गया था।[53] 2 जनवरी, 2018 तक 32,00,431 घरों के निर्माण के लिए 49,562 करोड़ रुपए की कुल केंद्रीय सहायता मंजूर की गई है।[54] ▪ मंजूर किए गए 9% घर बनकर तैयार हुए और मंजूर की गई 24% केंद्रीय सहायता जारी की गई। [54] ▪ शुरुआत में इस योजना में केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग के लोग शामिल थे। फरवरी 2017 में योजना के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के घटक के लाभ को मध्य आय वर्ग तक बढ़ाया गया।[55] **तालिका 8: पीएमएवाई-शहरी के अंतर्गत प्रगति[54]** | **2014-15** | **2015-16** | **2016-17** | **2017-18** **जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रु. में)** | 1,093 | 1,259 | 4,598 | 5,095 **निर्मित मकान** | 2,506 | 18,706 | 66,985 | 2,07,794 Note: For 2017-18, data updated till January 2, 2018.

2016-17 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत 47,000 करोड़ रुपए से अधिक आबंटित किए गए जोकि इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे बड़ी राशि है	▪ 2017-18 में मनरेगा के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी कुल राशि को बढ़ाकर 50,009 करोड़ रुपए कर दिया गया। 2016-17 में यह राशि 47,412 करोड़ रुपए थी।[56] ▪ मनरेगा स्पष्ट करता है कि मस्टर रोल के समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर वेतन भुगतान कर दिया जाना चाहिए।[57] भुगतान में विलंब को 16वें दिन से कैलकुलेट किया जाता है। ▪ योजना के अंतर्गत लंबित भुगतान का प्रतिशत 2014-15 में 73% से घटकर 2017-18 में 14% हो गया।[58] **तालिका 9: लंबित भुगतान का प्रतिशत और संयोजन[58]**

वर्ष	लंबित भुगतान का %	लंबित भुगतान का संयोजन (%)			
		> 90 दिन	60-90 दिन	30-60 दिन	15-30 दिन
2014-15	73	18.6	13.7	30.8	36.8
2015-16	66	6.2	9.3	31.2	53.3
2016-17	56	25	15	28	32
2017-18	14	5	6	25	63

Note: For 2017-18, data is updated till January 24, 2018.

2015-2020 की अवधि के दौरान ग्राम पंचायतों को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय संसाधन ट्रांसफर किए गए	▪ बुनियादी सेवाएं प्रदान करने और पंचायतों के व्यय एवं प्राप्तियों के विश्वसनीय डेटाबेस को बनाने में इस राशि का प्रयोग किया जाएगा।[59] 2017-18 तक ग्राम पंचायतों के कुल आबंटन में से 82% राशि को जारी किया गया।[60] **तालिका 10: ग्राम पंचायतों को आबंटन और जारी राशि[60]**

अवधि	आबंटन (करोड़ रु. में)	जारी की गई राशि (करोड़ रु. में)
2015-16	21,624	21,510 (99%)
2016-17	33,871	32,029 (94%)
2017-18	39,041	23,830 (61%)

Note: For 2017-18, data updated till January 1, 2018.

परिवहन

रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए सर्वाधिक 1.21 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत परिव्यय प्रदान किया गया

- भारतीय रेलवे श्वेत पत्र, 2015 के अनुसार, 4500 किलोमीटर के ट्रैक्स को हर वर्ष रीन्यू किया जाना चाहिए।[61] 2014-15 और 2017-18 के बीच रीन्यूअल का जो औसत लक्ष्य निर्धारित किया गया, वह श्वेत पत्र के सुझाव का 61% है। निम्नलिखित तालिका में 2014-15 से 2017-18 के बीच ट्रैक्स के लक्षित और वास्तविक रीन्यूअल को प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 11: ट्रैक रीन्यूअल : लक्ष्य बनाम उपलब्धियां (किलोमीटर में)[62]

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
लक्षित रीन्यूअल	2,200	2,500	2,668	3,600
वास्तविक रीन्यूअल	2,424 (110%)	2,794 (112%)	2,487 (93%)	2,007 (56%)

Note: Data for 2017-18 updated till November 2017.

- भारतीय रेलवे ने मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर का काम शुरू किया है।[63]
- 2017-18 में 4,000 रूट किलोमीटर के बिजलीकरण का लक्ष्य था। दिसंबर 2017 तक के आंकड़े के अनुसार, सरकार ने 2,367 रूट किलोमीटर (59%) के बिजलीकरण के काम को पूरा कर लिया है।[64]

उत्तर पूर्वी राज्यों में सभी मीटर गेज ट्रैक्स को ब्रॉड गेज ट्रैक में बदला जाएगा

- पिछले तीन वर्षों में, भारतीय रेलवे ने उत्तर पूर्व में शेष 900 किलोमीटर के मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदलने के काम को पूरा कर लिया और क्षेत्र में मीटर गेज शेष नहीं हैं।[65]

बारहमासी सड़कों को सभी ग्रामीण बसाहटों से जोड़ना। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 73,000 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र (एलिजिबल) बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है।[66]
- योजना के अंतर्गत 1.32 लाख बसाहटों को कवर करने का लक्ष्य था। योजना के प्रारंभ होने के बाद से लेकर अब तक 1.3 लाख बसाहटों (98%) को जोड़ा जा चुका है (23 जनवरी, 2018 तक)।[67] निम्नलिखित तालिका में यह प्रदर्शित किया गया है कि लक्ष्य की तुलना में कितने किलोमीटर सड़क बनकर तैयार हुई है।

तालिका 12: पीएमजीएसवाई के अंतर्गत प्रगति (किलोमीटर में)[68]

अवधि	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
लक्षित सड़क की लंबाई	21,775	33,649	48,812	51,000

निर्मित सड़क की लंबाई	38,056 (175%)	35,155 (104%)	47,446 (97%)	25,773 (51%)

Note: For 2017-18, the data is updated till January 24, 2018. The length includes new connectivity roads and upgradation of existing roads under PMGSY I and PMGSY II.

राष्ट्रीय सिविल एविएशन नीति से छोटे शहरों और कस्बों में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा

- राष्ट्रीय सिविल एविएशन नीति, 2016 के अनुसार, सस्ती क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अक्टूबर 2016 में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस)-उड़ान शुरू की गई।[69]
- योजना के अंतर्गत बोली प्रक्रिया के जरिए चुने हुए एयरलाइन ऑपरेटरों को सहयोग प्रदान किया जाता है। बोली प्रक्रिया के पहले दौर में सरकार ने पांच चुनी हुई एयरलाइन्स के 27 प्रस्तावों को 'लेटर ऑफ अवार्ड्स' जारी किए जोकि 43 आरसीएस एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करेंगे।[70] इनमें से 14 कम सेवा वाले/सेवा रहित एयरपोर्ट्स में ऑपरेशंस शुरू हो गए हैं।[71]

महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जोकि बाल लिंगानुपात में गिरावट के मुद्दे से संबंधित है, के उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) को वर्तमान में चुने हुए 161 जिलों में लागू किया गया है।[72] नवंबर 2017 में केंद्र सरकार ने 2017-18 और 2019-20 के दौरान 1,132 करोड़ रुपए के प्रस्तावित परिव्यय के साथ में इस योजना को पूरे देश में (सभी 640 जिलों में) लागू करने को मंजूरी दी थी। इस योजना को शत प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्राप्त होगी।[73]
- 2017-18 में इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए आबंटित किए गए।[74] पिछले चार वर्षों में योजना की वित्तीय प्रगति का विवरण निम्नलिखित तालिका में है।

तालिका 13: बीबीबीपी के अंतर्गत वित्तीय प्रगति (करोड़ रुपए में)[72,74]

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आबंटित राशि	34.8	59.3	43	200
जारी की गई राशि	13.3	39	2.9	25.3
जारी की गई राशि का %	38%	66%	7%	13%

Note: For 2017-18, data updated till December 15, 2017. Figures for 2016-17 and 2017-18 are revised and budget estimates, respectively.

लड़कियों के भविष्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक करोड़ रुपए से अधिक के खाते खोले गए और 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की गई	▪ हालिया आंकड़ों के अनुसार, 21 जुलाई, 2017 तक 15,849 करोड़ रुपए की जमा राशि वाले 1.1 करोड़ खाते खोले गए।[75]
मिशन इंद्रधनुष 'हर बच्चे को हर जगह' रोकथामकारी बीमारियों के टीके लगाने के प्रति प्रतिबद्ध है। इससे अब तक 55 लाख बच्चों को लाभ प्राप्त हुआ है	▪ 15 दिसंबर, 2017 तक 528 जिलों को कवर करते हुए चार चरण में मिशन इंद्रधनुष अभियान संचालित किया गया। इस दौरान 67 लाख से अधिक बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया।[76] ▪ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 8 अक्टूबर, 2017 को तीव्र मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया जिसका उद्देश्य दिसंबर 2018 तक पूर्ण टीकाकरण के कवरेज को 90% तक पहुंचाना है।[76] यह 24 राज्यों में संचालित किया जाएगा।[76]
गरीबों को सस्ती कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को शुरू किया गया	▪ दिसंबर 2017 तक योजना के अंतर्गत 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3,013 जन औषधि केंद्र सस्ती कीमतों पर दवाएं उपलब्ध करा रहे थे।[77] इस योजना का लक्ष्य मार्च 2017 तक 3,000 केंद्रों को स्थापित करना था।[77] ▪ 2018-19 और 2019-20 के दौरान प्रति वर्ष 1,000 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।[78]
गर्वनेंस और कानूनी सुधार	
1,100 से अधिक अप्रासंगिक कानूनों को रद्द किया गया है और 400 कानून रद्द होने की प्रक्रिया में हैं	▪ अपनी रिपोर्ट में विधि आयोग ने सुझाव दिया कि कुल 288 पुराने कानूनों को कानून की किताबों से निरस्त कर दिया जाए।[79] ▪ 2014-15 से जुलाई 2017 तक सरकार ने विधि निर्माण के जरिए 1,175 एक्ट्स को रद्द कर दिया है।[80] ▪ दिसंबर 2017 में संसद ने 136 एक्ट्स को रद्द करने वाले दो बिल्स को पारित किया था।[81,82]
एक साथ चुनावों और चुनावों के वित्त पोषण पर चर्चा	▪ फाइनांस बिल, 2017 ने प्रस्ताव रखा कि राजनीतिक दल एक व्यक्ति से अधिकतम 2,000 रुपए का नकद चंदा प्राप्त कर सकते हैं।[83] ▪ फाइनांस बिल, 2017 ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की योजना को प्रस्तावित किया।[83] सरकार ने 2 जनवरी, 2018 को योजना को अधिसूचित किया।[84] नो योर कस्टमर की शर्त को पूरा करने के बाद किसी भी मूल्य (1,000 रुपए, 10,000 रुपए,

	1,00,000 रुपए, 10,00,000 रुपए और 1,00,00,000 रुपए के मल्टीपल्स में) के इलेक्टोरल बॉन्ड को भारतीय स्टेट बैंक की विशेष शाखाओं से खरीदा जा सकता है। इन बॉन्ड्स पर पेई का नाम नहीं होगा और इनका जीवन काल केवल 15 दिन होगा, जिस दौरान इन्हें राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।[84]
कृषि, खाद्य और जल सुरक्षा	
सॉयल हेल्थ काड्र्स के जरिए उत्पादकता में सुधार	▪ योजना के अंतर्गत हर दो वर्षों में किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे जाते हैं। 16 जनवरी, 2018 तक के आंकड़ों के अनुसार, 2015-17 के दौरान 10.2 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड (चक्र 1 के लक्ष्य का 86%) जारी किए गए और 2017-19 की अवधि में अब तक किसानों को 0.9 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं (चक्र 2 के लक्ष्य का 14%)। इस पर 368.3 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।[85,86]
ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) के जरिए बाजार और लाभकारी मूल्यों का आश्वासन	▪ अप्रैल 2016 में ई-नाम योजना को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य मार्च 2018 तक 585 मार्केट्स के जरिए ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाना है। अक्टूबर 2017 तक, 14 राज्यों के 470 मार्केट्स को ई-नाम पोर्टल से जोड़ दिया गया था।[87,88]
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने रिस्क कवरेज का दायरा बढ़ाया, बीमायुक्त राशि को दोगुना किया और अब तक के सबसे कम प्रीमियम को आसान बनाया	▪ खरीफ 2016 (जुलाई-अक्टूबर) और रबी 2016-17 (अक्टूबर-मार्च) के दौरान इस योजना को 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत 5.7 करोड़ किसानों को कवर किया गया।[89] ▪ दिसंबर 2017 तक इस योजना के अंतर्गत 2 लाख करोड़ की कुल राशि का बीमा किया गया।[89]
प्रति बूंद अधिक फसल और हर खेत को पानी पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को विस्तार मिला है। पिछले दो वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 12.7 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र को कवर किया गया	▪ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को 2015 में आरंभ किया गया था। सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करने और पानी के कुशल उपयोग को बढ़ाने के लिए इस योजना को लागू किया जा रहा है।[90] ▪ 18 जनवरी, 2017 तक के आंकड़ों के अनुसार, 2015 से लघु सिंचाई के अंतर्गत 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आता है।[91]2017-18 में 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लक्ष्य की तुलना में 5.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र (45%) को कवर किया गया।[91]

रक्षा, गृह मामले और विदेशी मामले

आतंकवाद पर काबू पाना

घुसपैठ की कोशिशें, आतंकवादी हिंसा की घटनाएं और नागरिकों एवं सुरक्षाबलों की मौत अब भी गंभीर चिंता का विषय बनी हुई हैं

पिछले तीन वर्षों में वामपंथी अतिवादियों को नियंत्रित करने में सफलता मिली

- सितंबर 2017 में केंद्र सरकार ने 2017-18 से 2019-20 के दौरान पुलिस बलों के आधुनिकीकरण से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी। इस योजना में जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्यों और वामपंथ चरमपंथी प्रभावित राज्यों में आंतरिक सुरक्षा हेतु 10,132 करोड़ रुपए का केंद्रीय बजट परिव्यय शामिल था।[92]
- 12 दिसंबर, 2017 तक जम्मू कश्मीर में 203 आतंकवादी मारे गए, जबकि 2016-17 में मारे जाने वाले आतंकवादियों की संख्या 150 थी।[93] निम्नलिखित तालिका में 2014 से 2017 के दौरान आतंकवादी घटनाओं की संख्या प्रदर्शित की गई है।

तालिका 14: 2014-17 के दौरान आतंकवाद संबंधी घटनाएं[93,94,95]

वर्ष	आतंक की घटनाएं	मारे गए आतंकवादी	आत्मसमर्पण करने वाले/गिरफ्तार किए गए आतंकवादी	मारे गए नागरिक
2014	2,137	354	5,271	462
2015	1,871	346	4,281	234
2016	1,854	459	4,751	276
2017	1,424	390	3,628	259

Note: Includes terror incidents in Jammu and Kashmir, North East and LWE affected areas. Terrorists surrendered/arrested include data of North East and LWE affected areas.

भारतीय डायस्पोरा मजबूत करना

- भारतीय डायस्पोरा से अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने कई योजनाओं और कार्यक्रमों को शुरू किया जैसे ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम, नो इंडिया प्रोग्राम, प्रवासी भारतीय केंद्र, इत्यादि।[96]

हमारे पूर्व सैन्यकर्मियों की वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) की मांग पूरी हुई। इसका कुल वित्तीय प्रभाव लगभग 1,100 करोड़ रुपए का होगा। 6,200 करोड़ रुपए दो हिस्सों में जारी किए जाएंगे। इससे 19.6 लाख पूर्व सैन्यकर्मियों को लाभ प्राप्त होगा

- 31 दिसंबर, 2017 तक ओआरओपी एरियर्स के रूप में 10,739 करोड़ रुपए की राशि चुकाई गई।[97] निम्नलिखित तालिका में ओआरओपी की कार्यान्वयन संबंधी प्रगति को प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 15: ओआरओपी की कार्यान्वयन संबंधी प्रगति[97]

	पहली किस्त	दूसरी किस्त	तीसरी किस्त	चौथी किस्त
चुकाई गई राशि (करोड़ रुपए में)	4,161	2,397	2,321	1,860
लाभान्वित पूर्व सैन्यकर्मी	20,43,354	15,94,063	15,71,744	13,28,313

Note: The data is updated till December 31, 2017.

श्रम और रोजगार	
पहली बार कृषि और गैर कृषि क्षेत्र के न्यूनतम वेतन में 42% तक की वृद्धि हुई	▪ केंद्र सरकार ने गैजेट अधिसूचना के जरिए कृषि, गैर कृषि और निर्माण जैसे क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन को 40% तक बढ़ा दिया। गैर कृषि क्षेत्र में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन (प्रति दिन) 250 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए, अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए 437 रुपए और कुशल श्रमिकों के लिए 523 रुपए कर दिया गया।[98,99,100] ▪ अगस्त 2017 में लोकसभा में वेतन संहिता बिल 2017 प्रस्तुत किया गया। यह बिल वेतन और बोनस भुगतान को रेगुलेट करता है और चार एक्ट्स को रिप्लेस करते हुए उन्हें संहिता के अंतर्गत लाता है।[101] संहिता सभी श्रमिकों पर लागू होती है (संगठित और असंगठित क्षेत्र) और केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का प्रावधान करती है।[101]
युनाइटेड एकाउंट नंबर ने इंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड (ईपीएफ) की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की और इससे करोड़ों श्रमिकों के हितों की रक्षा हुई	▪ युनाइटेड एकाउंट नंबर की मदद से कर्मचारी नौकरियां बदलने की स्थिति में अपने प्रॉविडेंट फंड की जमा राशि को ट्रांसफर कर सकते हैं।[102] ▪ जनवरी 2017 से जून 2017 के बीच इंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने लगभग एक करोड़ अतिरिक्त कर्मचारियों को नामांकित किया।[103] ▪ दिसंबर 2017 तक यूनिवर्सल एकाउंट नंबर के जरिए संगठित क्षेत्र (12 करोड़ से अधिक कर्मचारी) अपने ईपीएफ खातों को पोर्टेबल बनाने में सक्षम हुआ।[103]
इंप्लॉयर्स बैंकों के जरिए अपने कर्मचारियों को वेतन देने में सक्षम	▪ वेतन भुगतान (संशोधन) बिल, 2017 को संसद में 2017 में पारित किया गया ताकि वेतन के भुगतान के लिए डिजिटल तरीकों को प्रयोग किया जा सके।[104]
मातृत्व लाभ एक्ट में संशोधन और मातृत्व अवकाश को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने से गर्भवती महिलाओं को मदद मिलेगी	▪ वैतनिक मातृत्व अवकाश को 12 हफ्ते से 26 हफ्ते करने के लिए 2017 में मातृत्व लाभ (संशोधन) एक्ट, 2017 को संसद में पारित किया गया।[105]
ऊर्जा	
स्वतंत्रता के बाद से 18,000 से अधिक गांव अंधेरे में जी रहे थे। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत इनमें से 11,000 से अधिक गांवों में बिजली पहुंचाई गई	▪ 2015 में सभी गांवों में बिजली पहुंचाने, किसानों को पर्याप्त बिजली सुनिश्चित करने और सभी उपभोक्ताओं को बिजली की नियमित आपूर्ति करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की गई।[106]

<table>
<tr><td></td><td>

- देश में बिजली रहित कुल गांवों (18,452) में से 82% गांवों को बिजलीकृत किया गया।[107] निम्नलिखित तालिका में योजना संबंधी प्रगति को प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 16: डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत बिजलीकृत गांवों की संख्या[107]

<table>
<tr><th></th><th>2015-16</th><th>2016-17</th><th>2017-18</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>बिजलीकृत गांवों की संख्या</td><td>7,108</td><td>6,015</td><td>2,060</td><td>15,183</td></tr>
</table>

Note: For 2017-18, the data is updated till November 30, 2017
</td></tr>
<tr><td>2,500 किलोमीटर लंबी जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा नेचुरल गैस पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) के साथ प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना शुरू की गई</td><td>

- पूर्वी राज्यों को प्राकृतिक गैस प्रदान करने हेतु सरकार 2,655 किलोमीटर के जेएचबीडीपीएल प्रॉजेक्ट के विकास के लिए 5,176 करोड़ रुपए का पूंजीगत अनुदान (12,940 करोड़ रुपए की कुल लागत का 40%) प्रदान करेगी।[108] यह पाइपलाइन बिहार, झारखंड, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से गुजरेगी।
- अक्टूबर 2017 में इस योजना के अंतर्गत सरकार ने भुवनेश्वर, ओड़िशा के 255 घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की आपूर्ति शुरू की।[109]
</td></tr>
<tr><td>2022 तक 175 गिगावॉट के लक्ष्य के मद्देनजर सरकार ने अपनी रीन्यूएबल ऊर्जा क्षमता 47 गिगावॉट तक बढ़ा ली</td><td>

- जनवरी से नवंबर 2017 के बीच 12 गिगावॉट की रीन्यूएबल एनर्जी क्षमता को शामिल किया गया और अब कुल मिलाकर 62 गिगावॉट की क्षमता हासिल कर ली गई है (2022 तक के लक्ष्य का 35%)।[110]
</td></tr>
<tr><td>उज्जवला (सभी को सस्ती एलईडी के जरिए उन्नत ज्योति) कार्यक्रम के अंतर्गत 20 करोड़ से अधिक के बल्ब वितरित किए गए</td><td>

- उज्जवला का लक्ष्य मार्च 2019 तक घरेलू उपभोक्ताओं को 77 करोड़ एलईडी बल्ब प्रदान करना है।[111]
- 26 दिसंबर, 2017 तक के आंकड़ों के अनुसार, 2017-18 के लिए 20 करोड़ एलईडी बल्बों के वितरण के लक्ष्य के मद्देनजर 5.5 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे जा चुके हैं। जनवरी 2015 से कुल 28 करोड़ एलईडीबल्ब बांटे जा चुके हैं (कुल लक्ष्य का 36%)।[111,112]
</td></tr>
<tr><td colspan="2">आदिवासी मामले</td></tr>
<tr><td>स्टैंड अप अभियान के अंतर्गत 2.5 लाख एससीज़ (अनुसूचित जातियों के लोगों), एसटीज़ (अनुसूचित जनजातियों के लोगों) और महिलाओं को सशक्त किया जाएगा</td><td>

- 2016 में स्टैंड अप इंडिया योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत बैंक प्रति शाखा कम से कम एक एससी या एक एसटी को और कम से कम एक महिला को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच ऋण देता है।[113]
</td></tr>
</table>

	▪ 22 दिसंबर, 2017 तक इस योजना के अंतर्गत 48,778 ऋण मंजूर किए गए। इनमें से महिलाओं को 81.7%, एससीज़ को 13.9% और एसटीज़ को 4.2% ऋण मंजूर किए गए।[114]
उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एससी/एसटी हब की शुरुआत की गई और 2016-20 के लिए 490 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आबंटन किया गया	▪ राष्ट्रीय एससी/एसटी हब नामक पहल अक्टूबर 2016 में शुरू की गई। यह हब केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों इत्यादि को वस्तुओं और सेवाओं की 4% आपूर्ति करने के लिए एससी/एसटी उद्यमियों को व्यावसायिक सहयोग प्रदान करता है।[115] ▪ 2016-17 से एससी/एसटी हब को 80 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।[116] **तालिका 17: राष्ट्रीय एससी/एससी हब के लिए वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)[116]** | | 2016-17 | 2017-18 | | **आबंटित** | 20 | 60 | Note: Figures for 2016-17 and 2017-18 are revised and budget estimates, respectively.
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत 300 में से 100 क्लस्टरों को आदिवासी क्षेत्रों में विकसित किया जाएगा	▪ 1 जनवरी, 2018 तक 29 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 300 में से 267 क्लस्टरों को चिन्हित और स्वीकृत किया गया है।[117] इसके अतिरिक्त 29 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 151 एकीकृत क्लस्टर एक्शन प्लान्स को मंजूरी दी गई है।[117] ▪ दिसंबर 2017 में उपलब्ध हालिया आंकड़े के अनुसार, आदिवासी क्षेत्रों में 19 क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं।[118] ▪ फरवरी 2016 से मिशन को 1,339 करोड़ रुपए जारी किए गए। 2017-18 में, जनवरी 2018 तक, 359 करोड़ रुपए (60%) जारी किए गए जबकि आबंटन 600 करोड़ रुपए का था। 2018-19 के लिए 1,200 करोड़ रुपए की बजट मंजूरी मिली है।[117]

<table>
<tr>
<td>आदिवासी उप योजना के अंतर्गत आबंटन में वृद्धि। आदिवासियों के सशक्तीकरण के लिए वनबंधु कल्याण योजना के अंतर्गत 14 विभिन्न क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है</td>
<td>

12 दिसंबर, 2017 तक आदिवासी उप योजना (टीएसपी) के अंतर्गत आबंटित राशि का 68% हिस्सा जारी किया गया।[119] उप योजना के लिए आबंटन 2014-15 में 1,040 करोड़ रुपए से बढ़कर 2017-18 में 1,350 करोड़ रुपए हो गया।[120,121]
2016-17 से आदिवासी लोगों के समग्र विकास के वनबंधु कल्याण योजना के उद्देश्यों को टीएसपी फंड्स के जरिए पूरा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत आबंटन में 91% की गिरावट हुई है। यह आबंटन राशि 2014-15 में 5,360 करोड़ रुपए थी और 2017-18 में 505 करोड़ रुपए।[120,121]

तालिका 18: योजना के अंतर्गत आबंटन (2015-18) (करोड़ रुपए में)[120,121]
<table>
<tr><th>आबंटन</th><th>2014-15</th><th>2015-16</th><th>2016-17</th><th>2017-18</th></tr>
<tr><td>आदिवासी उप योजना के अंतर्गत सहायता</td><td>1,040</td><td>1,132</td><td>1,200</td><td>1,350</td></tr>
<tr><td>वनबंधु कल्याण योजना</td><td>5,360</td><td>629</td><td>427</td><td>505</td></tr>
</table>
Note: Figures for 2016-17 and 2017-18 are revised and budget estimates, respectively.
</td>
</tr>
<tr>
<td>वन अधिकार एक्ट के अंतर्गत 55.4 लाख एकड़ क्षेत्र में लगभग 16.5 लाख व्यक्तिगत वन अधिकार टाइटिल दिए गए
47 लाख एकड़ से अधिक वन क्षेत्र में सामुदायिक वन अधिकार टाइटिल वितरित किए गए</td>
<td>

वन अधिकार एक्ट, 2006 के अंतर्गत 1.3 करोड़ एकड़ के क्षेत्र पर 18 लाख वन अधिकार टाइटिल्स प्रदान किए गए।[122]
निम्नलिखित तालिका 31 दिसंबर, 2016 से 31 अगस्त, 2017 की अवधि के दौरान वन अधिकार एक्ट की उपलब्धियों को प्रदर्शित करती है।

तालिका 19: वन अधिकार एक्ट के अंतर्गत उपलब्धियां[122]
<table>
<tr><th></th><th>प्राप्त हुए कुल दावे (व्यक्तिगत और सामुदायिक)</th><th>मान्य किए गए टाइटिलों की संख्या</th><th>वितरित किए गए टाइटिल्स के अंतर्गत वन भूमि (एकड़ में)</th></tr>
<tr><td>12 दिसंबर, 2016 तक स्थिति</td><td>41,69,962</td><td>17,47,507</td><td>1,22,93,137</td></tr>
<tr><td>2017 की उपलब्धियां</td><td>6,230</td><td>55,935</td><td>15,44,347</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>41,76,192</td><td>18,03,442</td><td>1,38,37,483</td></tr>
</table>
Note: The data for 2017-18 is updated till August 2017.
</td>
</tr>
</table>

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना सतत खनन तथा आदिवासियों की बेहतरी के लिए स्थानीय विकास सुनिश्चित करने का दोहरा लक्ष्य पूरा करेगी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) इस संबंध में एक पहल है	▪ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन द्वारा प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) को लागू किया जा रहा है। योजना के लिए डीएमएफ की धनराशि का ही उपयोग किया जा रहा है।[123] ▪ योजना के अनुसार, 60% धन राशि को उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है, जैसे: (i) पेय जल आपूर्ति, (ii) स्वास्थ्य सेवा, और (iii) शिक्षा, इत्यादि। **तालिका 20: 12 मुख्य राज्यों का कलेक्शन और आबंटन[123]** **डीएमएफ़ज़ के तहत एकत्र कुल राशि (करोड़ रु. में)** | **आबंटन (करोड़ रु. में)** | **प्रयुक्त (करोड़ रु. में)** | **प्रारंभ की गई योजनाओं की संख्या** कुल | 13,398 | 7,944 | 2,260 | 2,74,110 Note: The data for 2017-18 is updated till November 2017.
पर्यटन और संस्कृति	
पर्यटन मंत्रालय ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में थीमेटिक सर्किट को चिन्हित किया है	▪ 2014 से मंत्रालय पूरे देश में स्वदेश दर्शन योजना और राष्ट्रीय तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद) मिशन योजना के अंतर्गत थीम आधारित सर्किट विकसित कर रही है।[124] ▪ वर्तमान में दोनों योजनाओं के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 15 प्रॉजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2017-18 के लिए 1,301 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। 1 जनवरी, 2018 तक के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 703 करोड़ रुपए (54%) की राशि जारी की गई है।[125]
सांस्कृतिक विविधता का जश्न एक भारत श्रेष्ठ भारत	▪ एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत दो राज्यों को भागीदार बनाया जाता है ताकि सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए वे परस्पर एक दूसरे के साथ तालमेल बढ़ाएं।[126] ▪ सरकार ने अक्टूबर 2017 से दिसंबर 2018 तक के लिए मासिक कार्य योजना तैयार की है, जिसमें शैक्षणिक, पर्यटन, खेल और युवाओं से संबंधित क्षेत्रों की गतिविधियां शामिल हैं।[127] वर्तमान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 16 जोड़ियां हैं।[127]

ई पर्यटन वीसा के दायरे में अल्पावधि के मेडिकल उपचार और व्यवसाय यात्रा को शामिल करने के लिए नई ई-वीसा नीति को व्यापक बनाया गया	▪ 10 जनवरी, 2018 तक 162 देशों के नागरिकों को ई-वीजा की सुविधा उपलब्ध है।[128] **तालिका 21: जारी किए गए ई-वीसा की संख्या (लाख में)[129]** जारी किए गए ई-वीजा: 2015: 5.2; 2016: 11.8; 2017: 9 Note: For 2017, the data is updated till August 8, 2017.
विज्ञान, इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम	
भारतनेट प्रॉजेक्ट के अंतर्गत, ऑप्टिकल फाइबल केबल्स अब 75,700 ग्राम पंचायतों को कवर करती हैं, जबकि मई 2014 में यह संख्या केवल 59 थी	▪ *भारतनेट* प्रॉजेक्ट का लक्ष्य सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2,50,000) को मार्च 2019 तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है।[130] ▪ 12 दिसंबर, 2017 तक 1,05,831 ग्राम पंचायतों (42%) को ऑप्टिकल फाइबर केबल्स से जोड़ा जा चुका है।[130]
भारत ने आठ ऑपरेशनल मिशन लॉन्च किए जिनमें मौसम, पृथ्वी अवलोकन (अर्थ ऑब्जरवेशन) संबंधी और दूरसंचार उपग्रह शामिल हैं	▪ फरवरी 2017 में एक साथ 104 सेटेलाइट्स को लॉन्च किया गया।[131] ▪ भारत के जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च वेहिकल मार्क II ने 5 मई 2017 को 2230 किलोग्राम के दक्षिण एशिया उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।[132] ▪ जीएसएलवी एमके III ने सबसे भारी जीसैट-19 का 5 जून, 2017 को परिचालन किया।[132] ▪ इसरो के पोलर सेटेलाइट लॉन्च वेहिकल ने 710 किलोग्राम के कार्टोस्टैट-2 सीरिज के रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट को, 30 सहयात्रियों वाले सेटेलाइट के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया।[133]

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

[1] President's Address 2017, http://presidentofindia.nic.in/speeches-detail.htm?491.
[2] Overview-Monetary Policy, Reserve Bank of India, https://www.rbi.org.in/scripts/FS_Overview.aspx?fn=2752.
[3] "Press Release Consumer Price Index Numbers on Base 2012=100 for Rural, Urban and Combined for the Month of December 2017", Ministry of Statistics and Programme Implementation, January 12, 2018, http://mospi.nic.in/sites/default/files/press_release/CPI_PR12jan17th.pdf.
[4] Union Budget at a Glance, 2017-18, http://indiabudget.nic.in/ub2017-18/bag/bag1.pdf.

[5] Union Government Accounts At A Glance, As at the end of November, 2017, Controller General of Accounts, Ministry of Finance, http://www.cga.nic.in/MonthlyReport/Published/11/2017-2018.aspx
[6] Union Government Accounts At A Glance, As at the end of March, 2017, Controller General of Accounts, Ministry of Finance, Union Government Accounts, Monthly Report, Controller General of Accounts, Ministry of Finance, http://164.100.158.190//writereaddata/MonthAccount/112017/DTL11718.HTM#FISCAL_DEFICIT, http://www.cga.nic.in/MonthlyReport/Published/3/2016-2017.aspx
7 "Developments in India's Balance of Payments during the first quarter of 2017-18", Reserve Bank of India, Press Release, September 15, 2017, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR752E 9EECC64C9804717AF9929068F2E9ECB.PDF.
[8] "Developments in India's Balance of Payments during the second quarter of 2017-18", Reserve Bank of India, Press Release, December 13, 2017, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR1618E210FEF7F02F4EA1B2850877DEFE6CDC.PDF.
[9] RBI Database, https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=home.
[10] Lok Sabha Unstarred Question No. 456, Ministry of Commerce and Industry, December 18, 2017, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/13/AU456.pdf.
[11] FDI Statistics, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Manufacturing, last accessed on January 16, 2018, http://dipp.nic.in/sites/default/files/FDI_FactSheet_Updated_September2017.pdf.
[12] "FDI policy further liberalized in key sectors, Cabinet approves amendments in FDI policy", Cabinet, Press Information Bureau, January 10, 2018, http://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1516118.
[13]. Table No. 160, Handbook of Statistics on the Indian Economy, Reserve Bank of India, https://www.rbi.org.in/Scripts/AnnualPublications.aspx?head =Handbook%20of%20Statistics%20on%20Indian%20Economy.
[14] RBI Annual Report 2016-17, August 30, 2017, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/AnnualReport/PDFs/RBIAR201617_FE1DA2F97D61249B1B21C4EA66250841F.PDF.
[15] Status of the Return of SBNs – Reserve Bank of India (RBI) Annual Report 2016-17, Ministry of Finance, Press Information Bureau, August 30, 2017, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=170379.
[16] Lok Sabha Unstarred Question No. 1319, Ministry of Finance, December 22, 2017, http://164.100.47.194/Loksabha/Questions/QResult15.aspx?qref=59329&lsno=16.
[17] "GST roll-out – Complete transformation of the Indirect Taxation Landscape; Some minute details of how it happened, Ministry of Finance", Press Information Bureau, June 30, 2017, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=167023.
[18] Union Government Accounts At A Glance, As at the end of November, 2017, Ministry of Finance, http://www.cga.nic.in/MonthlyReport/Published/11/2017-2018.aspx.
[19] "Total collection under GST for the month of December 2017 has been Rs. 80,808 crores till 25th December 2017, Ministry of Finance" Press Information Bureau, December 26, 2017, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174827.
[20] "GST Revenue Figures – July 2017, Ministry of Finance" Press Information Bureau, August 29, 2017, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=170327.
[21] "GST Revenue Figures – As on 25th September, 2017, Ministry of Finance" Press Information Bureau, September 26, 2017, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=171142.
[22] "Rs 83,346 crores collected under GST for the month of October 2017, received in November (upto 27th Nov 2017), Ministry of Finance" Press Information Bureau, November 27, 2017, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=173899.
[23] "GST Revenue Collection Figures stand at Rs.92,150 crore as on 23rd October, 2017, Ministry of Finance", Press Information Bureau, October, 24, 2017, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=171882
[24] "Only Rs. 5,000 cr deposited under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana: Hasmukh Adhia", The Hindu Business Line, Jnue 1, 2017, http://www.thehindubusinessline.com/economy/only-rs-5000-cr-deposited-under-pradhan-mantri-garib-kalyan-yojana-hasmukh-adhia/article9717564.ece.
[25] "Official data for PMGKY: Unaccounted funds at just Rs 5000 crore", The Indian Express, June 2, 2017, http://indianexpress.com/article/business/official-data-for-pmgky-unaccounted-funds-at-just-rs-5000-crore-4685089/.
[26] 'Doing Business 2018', World Bank, http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf.
[27] 'Doing Business 2017', World Bank, http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Full-Report.pdf.
[28] Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, http://www.prsindia.org/billtrack/the-insolvency-and-bankruptcy-bill-2015-4100/.
[29] G.S.R. 436 (E), G.S.R. 437 (E) and G.S.R. 438 (E), Gazette of India, Ministry of Labour and Employment, May 4, 2017, http://labour.gov.in/sites/default/files/Notifications%20for%20amendment%20under%20EPF%2C%20EPS%20and%20EDLI%20Schemes%20for%20e-Payment_0.pdf.
[30] Finance Bill, 2017, http://www.prsindia.org/billtrack/the-finance-bill-2017-4681/; Memorandum explaining the provisions of the Finance Bill, 2017, http://unionbudget.nic.in/ub2017-18/memo/memo.pdf.
[31] Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Progress Report, last accessed on January 25, 2018, https://www.pmjdy.gov.in/account.
[32] Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Archive, last accessed on January 25, 2018, https://www.pmjdy.gov.in/Archive.
[33] "Key Achievements: 2017, Ministry of Electronics and IT", Press Information Bureau, December 29, 2017, http://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1514598.
[34] Direct Benefit Transfer, Government of India, last accessed on January 25, 2018, https://dbtbharat.gov.in/.
[35] Pradhan Mantri Mudra Yojana, last accessed on January 23, 2018, https://www.mudra.org.in/.
[36] PAHAL-Direct Benefits Transfer for LPG(DBTL) Consumers Scheme Ministry of Petroleum and Natural Gas, last accessed on January 15, 2018, http://petroleum.nic.in/dbt/whatisdbtl.html.
[37] Rajya Sabha Unstarred Question No. 1889, Ministry of Petroleum and Natural Gast, January 3, 2018, http://164.100.47.5/qsearch/QResult.aspx.
[38] Rajya Sabha Unstarred Question No. 1893, Ministry of Petroleum and Natural Gast, January 3, 2018, http://164.100.47.5/qsearch/QResult.aspx.
[39] Lok Sabha Unstarred Question No. 2536, Ministry of Communications, January 3, 2018, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/13/AU2536.pdf.
[40] Lok Sabha Starred Question No. 400, Ministry of Communications, March 29, 2017, http://164.100.47.194/Loksabha/Questions/QResult15.aspx?qref=50767&lsno=16.
[41] "Key Achievements: 2017, Ministry of Electronics and IT", Press Information Bureau, December 29, 2017, http://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1514598.
[42] "Swachh Bharat Mission needs to become a Jan Andolan with participataion from every stakeholder: Hardeep Puri
1,789 Cities have been declared ODF conference on PPP model for waste to energy projects", Ministry of Housing and Urban Affairs, Press Information Bureau, November 30, 2017, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=173995.
[43] "PM launches Swachh Bharat Abhiyaan", Prime Minister's Office, Press Information Bureau, October 2, 2014, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=110247.
[44] Swachh Bharat Urban, Ministry of Housing and Urban Affairs, last accessed on January 25, 2018, http://swachhbharaturban.gov.in/writereaddata/Statewise_status_of_implementation.pdf.
[45] Swachh Bharat Mission (Gramin), Ministry of Drinking Water and Sanitation, last accessed on January 23, 2018. http://sbm.gov.in/sbmdashboard/IHHL.aspx.
[46] Swachh Bharat Mission (Gramin), Ministry of Drinking Water and Sanitation, last accessed on January 23, 2018, http://sbm.gov.in/sbmReport/Report/Physical/SBM_VillageODFMarkStatus.aspx.
[47] "Union Cabinet approves Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation and Smart Cities Mission to drive economic growth and foster inclusive urban development", Press Information Bureau, Cabinet, April 29, 2015, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=119925.
[48] "Silvassa tops the List of Winner Cities--Erode, Diu, Biharsharif, Itanagar & Kavaratti selected in Round 4 of Smart Cities--Bareilly, Moradabad & Saharanpur in UP also selected—99 Smart Cities selected so Far, Ministry of Housing and Urban Affairs", Press Information Bureau, January 19, 2018, http://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1517205.

[49] Lok Sabha Starred Question No. 211, Ministry of Housing and Urban Affairs, January 2, 2018, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/13/AS211.pdf.
[50] Rajya Sabha Starred Question No. 106, Ministry of Housing and Urban Affairs, December 28, 2017, http://164.100.158.235/question/annex/244/As106.pdf.
[51] " PM Launches "Housing for All" in Rural Areas", Ministry of Rural Development, Press Information Bureau, November 20, 2016, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=153931.
[52] Pradhan Mantri Awas Yojana- Gramin, Ministry of Rural development, last accessed on January 24, 2018, http://rhreporting.nic.in/netiay/PhysicalProgressReport/physicalprogressreport.aspx.
[53] "Housing for All by 2022" Mission - National Mission for Urban Housing", Press Information Bureau, June 17, 2015, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=122576.
[54] Lok Sabha Unstarred Question No.2528, Ministry of Housing and Urban Affairs, January 2, 2018, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/13/AU2528.pdf.
[55] "Introduction of a new CLSS for Middle Income Group", Cabinet, Press Information Bureau, February 2017, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=157827.
[56] MGNREGS At a Galnce, Ministry of Rural Development, last accessed on January 26, 2018, http://mnregaweb4.nic.in/netnrega/all_lvl_details_dashboard_new.aspx.
[57] Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005, Operational Guideline 2008, http://nrega.nic.in/Nrega_guidelinesEng.pdf.
[58] MGNREGS MIS Reports, Ministry of Rural Development, last accessed on January 24, 2018 http://www.nrega.nic.in/netnrega/home.aspx.
[59] Rajya Sabha Unstarred Question No.1522, Ministry of Panchayat Raj, January 1, 2018, http://164.100.158.235/question/annex/244/Au1522.pdf.
[60] Rajya Sabha Unstarred Question No.1522, Ministry of Panchayat Raj, January 1, 2018, http://164.100.158.235/question/annex/244/Au1522.pdf.
[61] Indian Railways Lifeline of a Nation (A White Paper, Ministry of Railways, February 2015, http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/finance_budget/Budget_2015-16/White_Paper-_English.pdf.
[62] "Status of Track Renewal in Railways", Ministry of Railways, Press Information Bureau, December 29, 2017, http://pib.nic.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1514627.
[63] Lok Sabha Starred Question No.2680, Ministry of Railways, January 3, 2018, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/13/AU2680.pdf.
[64] "Year End Review 2017 of Ministry of Railways", Ministry of Railways, Press Information Bureau, December 29, 2017, http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1514686.
[65] "Railways continues its emphasis on improvement in Railways infrastructure in the North- eastern region", Press Information Bureau, Ministry of Railways, June 23, 2017, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=166855.
[66] PMGSY Guidelines, Ministry of Rural Development, last accessed on January 18, 2018. http://pmgsy.nic.in/.
[67] Online Management, Monitoring and Accounting System (OMMAS), Pradhan Mantri, Gram Sadak Yojana, last accessed on January 23, 2018, http://omms.nic.in/Home/CitizenPage/#.
[68] Online Management, Monitoring and Accounting System (OMMAS), Pradhan Mantri, Gram Sadak Yojana, last accessed on January 23, 2018 http://omms.nic.in/Home/CitizenPage/#.
[69] Rajya Sabha Unstarred Question No. 329, Ministry of Civil Aviation, December 19, 2017, http://164.100.47.5/qsearch/QResult.aspx.
[70] Rajya Sabha Unstarred Question No. 329, Ministry of Civil Aviation, December 19, 2017, http://164.100.47.5/qsearch/QResult.aspx.
[71] Rajya Sabha Unstarred Question No. 1142, Ministry of Civil Aviation, December 21, 2017, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/13/AU1142.pdf.
[72] Lok Sabha Unstarred Question No 153, Ministry of Women and Child Development, December 15, 2017, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/13/AU153.pdf.
[73] "Year End Review, Ministry of Women & Child Development", December 29, 2017, http://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1514702.
[74] Demand for Grants, Ministry of Women and Child Development, 2017-18, http://www.indiabudget.gov.in/ub2017-18/eb/sbe99.pdf.
[75] Lok Sabha Unstarred Question No 1138, Ministry of Women and Child Development, July 21, 2017, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/12/AU1138.pdf.
[76] Lok Sabha Unstarred Question No 162, Ministry of Health and Family Welfare, December 15, 2017, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/13/AU162.pdf.
[77] "3,013 Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP) Kendras functional in 33 States/UTs, Ministry of Chemicals and Fertilizers", December 19, 2017, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174500.
[78] Lok Sabha Unstarred Question No 669, Ministry of Chemicals and Fertilizers, December 19, 2017, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/13/AU669.pdf.
[79] "Obsolete Laws: Warranting Immediate Repeal (Fourth Interim Report)", Report No. 251, Law Commission of India, November 2014, http://lawcommissionofindia.nic.in/reports/Report_No.251%20on%20Obsolete%20Laws%20-%20Warrnting%20immediate%20Repeal%20(Fourth%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Interim).pdf.
[80] Lok Sabha Unstarred Question No.1810, Ministry of Law and Justice, July 26, 2017, http://164.100.47.194/Loksabha/Questions/QResult15.aspx?qref=54988&lsno=16.
[81] The Repealing and Amending Act, 2017, Ministry of Law and Justice, January 8, 2018, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2018/181637.pdf.
[82] The Repealing and Amending (Second) Act, 2017, Ministry of Law and Justice, January 8, 2018, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2018/181639.pdf.
[83] The Finance Act, 2017, March 31, 2017, http://egazette.nic.in/writereaddata/2017/175141.pdf.
[84] The Government of India notifies the Scheme of Electoral Bonds to cleanse the system of political funding in the country, Ministry of Finance, Press Information Bureau, January 2, 2018, http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1515123.
[85] Progress Report Cycle I and Cycle II, Soil Health Cards, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, January 16, 2018, http://soilhealth.dac.gov.in/.
[86] Rajya Sabha Unstarred Question No 1292, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, December 29, 2017, http://164.100.47.5/qsearch/QResult.aspx.
[87] Lok Sabha Unstarred Question No 1539, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, July 27, 2017 http://164.100.47.194/Loksabha/Questions/QResult15.aspx?qref=54625&lsno=16.
[88] National Agriculture Market, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, last accessed on January 11, 2017, http://www.enam.gov.in/NAM/home/index.html.
[89] Lok Sabha Unstarred Question No 58, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, December 19, 2017, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/13/AS58.pdf.
[90] Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, last accessed on January 24, 2018, http://pmksy.gov.in/#s1.
[91] Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Physical Progress Report, last accessed on January 23, 2018, http://pmksy.gov.in/microirrigation/Physical_Report.aspx.
[92] Cabinet approves umbrella scheme of Modernisation of Police Forces, Cabinet, Press Information Bureau, September 27, 2017, http://pib.nic.in/newsite/printrelease.aspx?relid=171164.
[93] Lok Sabha Unstarred Question No. 621, Ministry of Home Affairs, December 19, 2017, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/13/AU621.pdf.
[94] Lok Sabha Unstarred Question No. 621, Ministry of Home Affairs, December 19, 2017, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/13/AU621.pdf.
[95] Left Wing Extremism Division, Ministry of Home Affairs, last accessed on January 26, 2018, http://mha.nic.in/sites/upload_files/mha/files/LWE_16012018.PDF.
[96] Overseas Indian Affairs, Ministry of External Affairs, last accessed on January 18, 2018, http://www.mea.gov.in/diaspora-engagement.htm.
[97] "Status Report on implementation of OROP benefits as on 30.09.2017 and compiled up to 31.12.2017" Ministry of Defence, December 31, 2017, http://desw.gov.in/sites/default/files/orop-status-dec17.pdf.
[98] "Year End Review, Ministry of Labour and Employment", December 18, 2017, http://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1512998.
[99] Rate of Minimum Wages, Ministry of Labour and Employment, March 1 2017, https://labour.gov.in/sites/default/files/MX-M452N_20170518_132440.pdf.
[100] Gazette Number 173, Ministry of Labour and Employment, January 19, 2017, Gazette of India, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2017/173724.pdf.
[101] The Code on Wages Bill 2017, Ministry of Labour and Employment, http://labour.gov.in/sites/default/files/Code%20on%20Wages%20Bill%202017-As%20introduced%20in%20Lok%20Sabha.pdf.
[102] Employee's Provident Fund Organisation, Ministry of Labour and Employment, http://www.epfindia.com/site_en/UAN_Services.php.

[103] "Year End Review, Ministry of Labour and Employment", December 18, 2017, http://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1512998.
[104] The Payment of Wages (Amendment) Bill, 2017, Ministry of Labour and Employment, http://164.100.47.4/billstexts/lsbilltexts/PassedBothHouses/payment%20wage-House-242.pdf.
[105] The Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017, Ministry of Law and Justice, https://labour.gov.in/sites/default/files/Maternity%20Benefit%20Amendment%20Act,2017%20.pdf.
[106] "Prime Minister to Launch Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana in Patna", Ministry of Power, Press Information Bureau, July 23, 2015, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=123595.
[107] Lok Sabha Starred Question No. 89, Ministry of Power, December 21, 2017, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/13/AS89.pdf.
[108] Rajya Sabha Unstarred Question No. 1084, Ministry of Petroleum and Natural Gas, December 27, 2017, http://164.100.47.5/qsearch/QResult.aspx.
[109] "Shri Dharmendra Pradhan launches Piped Natural Gas (PNG) supply in Bhubaneswar, Ministry of Petroleum and Gas", Press Information Bureau, October 20, 2017, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=171830.
[110] "Year End Review 2017, Ministry of New and Renewable Energy, Press Information Bureau, December 27, 2017, http://pib.nic.in/newsite/pmreleases.aspx?mincode=28.
[111]"National Led Bulbs Scheme Gets a New Face un UJALA", Press Information Bureau, Ministry of Power, March 11, 2016, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=137826.
[112] Lok Sabha Unstarred Question No. 2838, Ministry of Power, January 4, 2018, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/13/AU2838.pdf.
[113] Lok Sabha Starred Question No. 178, Ministry of Finance, December29, 2017, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/13/AS178.pdf.
[114] Rajya Sabha Starred Question No. 45, Ministry of Finance, December 19, 2017 http://164.100.47.5/qsearch/QResult.aspx.
[115] "Vice President Inaugurates National SC ST Hub (NSSH) Confluence, MOUs with 3 Sector Skill Councils to provide skill development trainings to SC-ST Entrepreneurs, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Press Information Bureau, September 20, 2017, http://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1503470.
[116] Notes on Demand for Grants, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, 2017-18, http://indiabudget.nic.in/ub2017-18/eb/sbe64.pdf
[117] Lok Sabha Unstarred Question No 1549, Ministry of Rural Development, January 1, 2018, http://164.100.158.235/question/annex/244/Au1549.pdf.
[118] List of Rurban Clusters approved, Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission, last accessed on December 31, 2017, http://rurban.gov.in/download/List_of_Approved_Clusters.pdf.
[119] "Year End Review 2017, Ministry of Tribal Affairs", Press Information Bureau, December 27, 2017, http://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1514250.
[120] Note on Demand for Grants, 2016-17, Ministry of Tribal Affairs, https://openbudgetsindia.org/dataset/fc4c785e-a785-4cba-a960-80700fd0f1ed/resource/b0a81210-37ce-46d2-97fb-497641cb619e/download/ministry-of-tribal-affairs.pdf.
[121] Notes on Demand for Grants, Ministry of Tribal Affairs, 2017-18, http://www.indiabudget.gov.in/ub2017-18/eb/sbe96.pdf.
[122] "Year End Review 2017, Ministry of Tribal Affairs", Press Information Bureau, December 27, 2017, http://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1514250.
[123] Lok Sabha Unstarred Question No 2870, Ministry of Mines, January 4, 2018, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/13/AU2870.pdf.
[124] "Year End Review- 2017: Ministry of Tourism", Press Information Bureau, Ministry of Tourism, December 28, 2017, http://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1514505.
[125] Lok Sabha Unstarred Question No.2221, Ministry of Tourism, January 1, 2018, http://164.100.47.190/loksabhaquestions/annex/13/AU2221.pdf.
[126] "Ek Bharat Shreshtha Bharat, Ministry of Human Resource Development, Press Information Bureau, March 27, 2017, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=159986.
[127] Rajya Sabha Unstarred Question No. 716, Ministry of Human Resource Development, December 19, 2017, http://164.100.47.5/qsearch/QResult.aspx.
[128] e-visa, Government of India, last accessed on January 10, 2018, https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html.
[129] Lok Sabha Unstarred Question No. 3587, Ministry of Home Affairs, August 8, 2017, http://164.100.47.194/Loksabha/Questions/QResult15.aspx?qref=56857&lsno=16.
[130] Lok Sabha Unstarred Question No. 916, Ministry of Communications, December 20, 2017, http://164.100.47.194/Loksabha/Questions/QResult15.aspx?qref=58814&lsno=16.
[131] Rajya Sabha, Unstarred Question No. 2049, Department of Space, January 4, 2018, http://164.100.47.4/newrsquestion/ShowQn.aspx.
[132] "Year End Review: Department of Space", Department of Space, Press Information Bureau, December 26, 2017, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174820.
[133] "PSLV successfully launches 31 satellites in a single flight", Department of Space, Press Information Bureau, January 12, 2018, http://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1516510.